टैरिफ के असर को कम करने के लिए आएगी नई निर्यात पॉलिसी

NBT रिपोर्ट, लखनऊ : यूपी के निर्यात पर होने वाले अमेरिकी टैरिफ के असर को कम करने के लिए राज्य सरकार नई निर्यात पॉलिसी लाने की तैयारी कर रही है। इस निर्यात पॉलिसी में निर्यातकों के लिए कई तरह की रियायतें दी जाएंगी, जिससे निर्यातकों के होने वाले नुकसान को कम किया जा सके और अमेरिकी टैरिफ के बाद निर्यातकों को नए बाजार तलाशने में किसी तरह की समस्या न आए। नई पॉलिसी के तहत एक निर्यात संवर्धन कोष बनेगा। इसका उपयोग वैश्विक सम्मेलनों में ब्रैंड यूपी को बढ़ावा देने में किया जाएगा। साथ ही ऐसे निर्यातक जिनका निर्यात का 60-70% हिस्सा अमेरिका को निर्यात होता है, उनके लिए पॉलिसी में विशेष प्रावधान किया जाएगा। साथ ही निर्यात को परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव से जोड़ा जाएगा।

> निर्यातकों को होने वाले नुकसान को कम करने का होगा प्रयास

ये सुविधाएं मिल सकती है : नई नीति के तहत मार्केट डिवेलपमेंट असिस्टेंस को ₹3 लाख से बढ़ाकर ₹5 लाख किया जा सकता है। साथ ही यूपी सरकार हर निर्यातक इकाई के लिए सहायता की राशि को बढ़ाकर ₹25 लाख सालाना कर सकती है। मौजूदा समय में ये करीब ₹16 लाख है। निर्यातकों को प्रमुख बंदरगाहों तक माल परिवहन के लिए हर साल ₹30 लाख तक का प्रोत्साहन दिया जा सकता है। विमान लोडिंग के लिए हर साल ₹10 लाख तक के अनुदान का प्रावधान किया जा सकता है। कुरियर के जरिए जो सैंपल दूसरे देशों में भेजे जाते हैं, उस पर मिलने वाली सब्सिडी को भी बढ़ाया जाएगा। दुनियाभर में होने वाले ट्रेड शो में प्रतिभाग करने के लिए प्रतिभागियों को स्टॉल लगाने पर ₹3.25 लाख तक की कुल लागत का 75% सरकार देगी। निर्यात प्रतिभागियों की हवाई यात्रा में सहायता दी जाएगी।

AI Image

FTA वाले देशो मे निर्यात बढ़ाने पर जोर : टैरिफ के बाद निर्यात में आई कमी को पूरा करने के लिए अब राज्य सरकार का फोकस ऐसे देशों पर है, जिनके साथ भारत का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। साथ ही कई ऐसे देश भी हैं, जहां उत्तर प्रदेश के उत्पादों की डिमांड तो है, लेकिन वहां अभी तक निर्यात बहुत कम होता है। उन देशों में निर्यात को बढ़ावा दिया जाएगा। राज्य सरकार का खास जोर स्पेन, इटली, ब्राजील, मलयेशिया जैसे देशों में निर्यात को बढ़ाना है।

ईज ऑफ डूइंग एक्सपोर्ट होगा लागू : ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की तर्ज पर ईज ऑफ डूइंग एक्सपोर्ट लागू किया जाएगा। इसमें मार्केट रिसर्च, मिशन निर्यात प्रगति, वन स्टाप डिजिटल इन्फॉर्मेशन हब स्थापित किया जाएगा। डिजिटल मार्केटिंग, ई-कॉमर्स और सोशल मीडिया पर इंसेंटिव दिया जाएगा।

'कई रियायतें देगी सरकार'

NBT रिपोर्ट, लखनऊ : अमेरिकी टैरिफ से यूपी के निर्यात पर होने वाले असर को कम करने के लिए राज्य सरकार ने तैयारियां तेज कर दी हैं। बुधवार को सीएम योगी ने टैरिफ और जीएसटी की दरों होने वाले बदलाव से राजस्व कलेक्शन पर पड़ने वाले असर को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान निर्यात को कुछ सहूलियतें दिए जाने पर चर्चा हुई, जिसकी घोषणा जल्द की जा सकती है। एक अन्य बैठक मे चर्चा हुई कि GST दर 5% और 18% होने के बाद इसे कैसे लागू किया जाएगा। इसको लेकर क्या तैयारियां है और अधिकारियों को इसके लिए कैसे प्रशिक्षित किया जाएगा।